LOK SABHA

Friday, June 16, 1967/Jyaistha 26, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नियंत्रण हटाये जाने के बाद इस्पात का मूल्य

\+

*541 श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम मूर्ति :
श्री प्र० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रा० स्वा० विद्यार्थी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री पार्थसारथी :
श्री कं० हाल्दर :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस्पात से नियंत्रण हटाये जाने से इस्पात की बनी वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है तथा इसके क्या कारण हैं,

(ख) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या देश में इस्पात का उत्पादन अब उस स्थिति पर पहुंच गया है कि नियंत्रण हटाये जाने से खुले बाजार में इस्पात के व्यापार में कोई कठिनाई नहीं होगी; और

(घ) क्या नियंत्रण हटाये जाने से पहले उनके मंत्रालय द्वारा किये गये अध्ययन तथा मांगों के सुझावों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-685/67]

Shri S. C. Samanta: May I know what results are perceptible at present after the de-control of all sorts of steel from 1st May, 1967?

Shri P. C. Sethi: Actually the categories in short supply will take about 3 to 4 months to stabilise, because production in those categories is likely to rise now and the position would be easier.

Shri S. C. Samanta: May I know for how long Government intends to study the working of decontrol and whether any other committee will be established for that purpose?

Shri P. C. Sethi: There is no idea of establishing any other committee, but we would like to see the market conditions for at least a few months and then we would come to a conclusion.

Shri Vasudevan Nair: In the statement Government has tried to explain away the whole thing by saying,

> "It is not correct, however, to say that the price increases have occurred as a result of decontrol."

But we find from the statement that the prices of all categories of steel have gone up. They have said that some items are in short supply and so there is some justification for prices going up. But what is the justification for the prices of all the items going up? May I know whether Government will seriously consider, in case this trend persists, going back on the present decision of decontrol?

Shri P. C. Sethi: We have said it because no increase in price was given to the steel industry since 1st March, 1964. Whether decontrol would have come or control would have remained, some price increase was due. That is why we said, there is no connection between the price increase and decontrol.

श्री मधु लिमये : स्टील के दामों में कुछ इजाफा अनिवार्य था चूंकि आवकारी वगैरह बढ़ गई थी । लेकिन इन्होंने जो तालिका दी है उस में कुछ चीजों के दाम तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं जैसे गैलवेनाइज्ड कौरोंगेटिड शीट्स 29 प्रतिशत, उसी तरह से व्हील एंड टायर्ड, फोल्ड डिजाइन 20 प्रतिशत, कोल्ड रोल्ड शीट्स बारह प्रतिशत, एक्सलज फोल्ड डिजाइन 21 प्रतिशत । क्या मंत्री महोदय खुलासा देंगे कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के कारण मूल्य वृद्धि कितनी समर्थनीय थी और उससे ज्यादा कितनी हुई है ? यदि ज्यादा है तो फिर एक सवाल उठता है अध्यक्ष महोदय अक्सर कहा जाता है, मुक्त व्यापार होना चाहिये, और मुक्त व्यापार होने से दाम गिरेंगे, यहां तो मुक्त व्यापार की इजाजत दी गई है फिर क्या कारण है कि इतने ज्यादा दाम बढ़ गए हैं । मैं पूंजीपतियों से भी जानना चाहता हूं कि आखिर मामला क्या है ? क्या कारण है कि मुक्त व्यापार जब होता है तो दाम गिराने के बजाय उनको बढ़ाते रहते हैं । मैं चाहता हूं कि इस बात का मंत्री महोदय खुलासा करें ।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक एक्साइज ड्यूटी और फेट का ताल्लुक है इनकी वजह से दामों में बढ़ोतरी पहले भी की जाती रही है । इस समय जो भावों में बढ़ोतरी की गई है खास तौर से कौरोंगेटिड शीट्स में, व्हीलज में और एक्सेल्ज में उसको मैं बता देता हूं । कौरोंगेटिड शीट्स में इजाफे का सब से बड़ा कारण यह है कि करीब 120 रुपये का फर्क जो जिंक इस्तेमाल होता है और जो इम्पोर्ट होता है उसकी प्राइस में पड़ गया है । करीब तीस रुपये का फर्क डिवैल्युएशन की वजह से पड़ा है । इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को कुछ एक्सपोर्ट के लिए सबसिडी भी देने वाले हैं । इन सब को देखते हुए जो इजाफा किया गया है वह बाजार के हालात को देखते हुए मुनासिब मालूम होता है ।

श्री आर० करनेन्डीज : ये जो दाम बढ़े हैं, मैं जानना चाहता हूं कि विदेशों से जो अलग अलग किस्म का सामान अभी भी हिन्दुस्तान में आयात किया जाता है, उसके भी दामों में यह बढ़ोतरी हुई है और हुई है तो किस परिणाम में हुई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह जो बढ़ोतरी की गई है यह तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

और प्राइवेट सैक्टर का जो इंडिजीनस स्टील है, उस में की गई है ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : यह कहा गया है कि कुछ ऐसी आइटम्ज हैं जिन का प्रोडक्शन जरूरत के मुताबिक नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जिन कैटेगरीज को अभी शार्टेज है उन में खास तौर से फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं, कोरोगेटिड शीट्स हैं, प्लेट्स आदि हैं । कोरोगेटिड शीट्स के प्रोडक्शन में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है । इसके लिए जिंक के लाइसेंस दिये गये हैं । यह आशा की जाती है कि दो तीन महीने में इन चीजों का प्रोडक्शन पहले से बढ़ेगा । लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो डिमांड है उसको हम मीट कर लेंगे ।

श्री मणिभाई जे० पटेल : मेरे दो सवाल हैं । एक तो यह है

"(1) What effect the Government has recorded in the internal market after de-control of steel;

दूसरा यह है :

(2) how many kinds of steel are still imported from abroad and what steps the Government is taking to produce them in this country."

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक बाजार में अवेलेबिलिटी का सवाल है जो फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं तथा इस तरह की दूसरी आइटम्ज हैं उनकी कमी अभी भी महसूस की जा रही है । जहां तक आयात का सवाल है, टूल्स एलाय, फ्लेट्स एंड शीट्स, फ्लैट प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट की जाती हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह समझा जाए कि स्टील के दामों में जो वृद्धि हुई है उससे सरकार सतुष्ट है और दामों को कम करने के लिये कोई भी कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक बढ़ोतरी का सवाल है अन्य चीजों की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी तुलना में जे० पी० सी० ने जो प्राइसिस को इनक्रीज किया है वह संतोषजनक प्रतीत होता है । यह खयाल है कि जो बढ़ोतरी की गई है उसकी वजह से अब कम से कम एक साल तक और कोई बढ़ोतरी नहीं होगी । इसका खयाल रखा जाएगा और बढ़ोतरी न हो, इसकी कोशिश की जाएगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कोई गारंटी दे सकते हैं ।

श्री प्र० चं० सेठी : साल भर नहीं होगी, ऐसा खयाल है ।

Mr. Speaker: Please sit down. Ministers should wait for the name to be called. They should not simply answer to whoever puts a question.

श्री कंवरलाल गुप्त : खास तौर से कौरोगेटिड शीट्स के मूल्यो में तथा एक्सेल्ज, पोल्ज डिजाइन के मूल्यों में वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है । इनके अलावा और भी चीजें इस लिस्ट में दी गई हैं । डिकंट्रोल के पहले भी इनकी ब्लैक मार्किट प्राइस बहुत ज्यादा थी, क्या यह बात ठीक है ? अगर ठीक है तो उस वक्त क्या प्राइस थी और उसके मुकाबले में अब प्राइस कुछ बढ़ी है, कम हुई है या उतनी ही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ब्लैक मार्किट प्राइस का तो ठीक से अंदाजा नहीं है । लेकिन यह कहा जाता है कि कौरोगेटिड शीट्स बाजार

में दो हजार से लेकर पच्चीस सौ रुपये टन के भाव से मिलती थीं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : अब क्या भाव है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ठीक पता नहीं है । ब्लैक मार्किट का तो अब सवाल नहीं है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : आज का भाव सफेद में बता दीजिये ।

श्री प्र० चं० सेठी : इसका भाव पंद्रह सौ टन के लगभग फिक्स है । लेकिन बाजार में शायद 1700—1800 के आसपास बिकती है ।

Shri Virendrakumar Shah: Sir, before I put my supplementary I would like to know whether my impression about a reply given by the Minister is correct. My question is based on that. Did the Minister say that there is no connection between price increase and de-control?

Shri P. C. Sethi: I did say, Sir, that as far as price increase is concerned even without de-control it was due.

Shri Virendrakumar Shah: Thereby he means that there is no connection between price increase and de-control. De-control came into effect on 1st May and price increase was announced on 2nd May after obtaining the approval of all ministries including the Steel Ministry of which the hon. Minister is in charge. If that is so, would it be a correct statement to make that there is no connection between price increase and de-control? May I also now whether Government have received representations from processing industries like re-rolling industry and engineering industry to the effect that this increase in price is high in the sluggish market, which the Government themselves have accepted, and that this is going to act further adversely?

Dr. Chenna Reddy: The position is there is no connection between the two. The increase in price was inevitable and it was inherent in the situation since 1964 when the prices were revised. Secondly, the prices for re-rollers and billets have been increased. Along with this increase, de-control has also been effected. Regarding the increase in the price of billets, to which the hon. Member has referred, it is a fact that the increase is there. JPC has been advised to examine the matter. It is under consideration.

Mr. Speaker: I would suggest that along with S. Q. No. 542, S.Q. Nos. 545 and 558 may also be taken up.

Corporation for closed Textile Units

*542. **Shri K. Ramani:**
Shri Mohammad Ismail:
Shri Umanath:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether some State Government have made proposals to establish a corporation to run the closed textile units taken over by Government;

(b) if so, the names of such State Governments and the main features of the proposals;

(c) whether Government have considered the proposals; and

(d) if so, the result thereof?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Yes, Sir

(b) The Government of Maharashtra in their Fourth Plan proposals proposed the setting up of a Textile Corporation for taking over the closed mills which are capable of being salvaged. They proposed an outlay of Rs. 5 crores for investment in the share capital of the proposed Corporation.

(c) and (d). Government are, themselves, proposing to set up a Textile Corporation to take over such textile mills.